मई दिवस ज़िंदाबाद!

आइए, श्रमजीवी वर्ग के सत्ताधारी वर्ग बनने के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं!

मई दिवस 2026 के मौके पर कामगार एकता कमिटी का आह्वान

मज़दूर साथियों!

1 मई - मई दिवस सभी देशों के मज़दूरों के लिए ऐतिहासिक और आज के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। “दुनिया के मज़दूरों, एक हो!” एक सदी से भी पहले का यह आह्वान आज भी हमारे दिलों में गूंज रहा है, और उसी भावना से हम पूंजीवादी शोषण और हर तरह के ज़ुल्म के खिलाफ़ लड़ाई में अपनी एकजुटता और इरादे को फिर से पक्का करते हैं।

मई दिवस ऐसे समय में आ रहा है जब दुनिया भर में करोड़ों मेहनतकश लोग अपने अधिकारों पर हमलों, ईरान और फ़िलिस्तीन के लोगों के खिलाफ़ छेड़े गए अन्यायी युद्धों और पूंजीपति वर्ग की सरकारों द्वारा ज़रूरी सेवाओं में कटौती के खिलाफ़ सड़कों पर उतर रहे हैं।

हमारी मेहनत ही तो है जो हिंदोस्तान की दौलत बना रही है, लेकिन हमें इतनी सी मज़दूरी दी जाती है कि गुज़ारा मुश्किल से ही चल पाता है। मज़दूरों की मेहनत का फल पूंजीपति उठा रहे हैं जो दिन-ब-दिन और अमीर होते जा रहे हैं।

दिल्ली के नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) के औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री के मजदूरों पर हाल में ही हुए पुलिस के द्वारा बर्बर हमले उन मुश्किल हालातों को दिखाती हैं जिनके खिलाफ मजदूर बगावत कर रहे हैं। ये उस बेरहम ज़ुल्म को दिखाती हैं जिसका सामना हम मजदूरों को अपने हक की मांग करने और उसके लिए लड़ने पर करना पड़ता है।

अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में, सार्वजनिक और निजी कंपनियों में, 10-12 घंटे से ज़्यादा काम करना आम बात हो गई है। इन सभी कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम बड़े पैमाने पर और खुलेआम हो रहा है। खाली जगहें नहीं भरी जा रही हैं, जिससे मजदूरों पर असहनीय दबाव पड़ रहा है। सुरक्षा मानकों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे भयानक हादसे हो रहे हैं। चार श्रम संहिताओं का मकसद इन सभी तरीकों को कानूनी बनाना और मजदूरों के मुश्किल से जीते गए कई अन्य हकों पर हमला करना है।

रेलवे, बिजली, बैंकिंग, बीमा, कोयला खदानों, टेलीकॉम, पेट्रोलियम, पोर्ट्स और दूसरी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के मजदूर, निजीकरण के कार्यक्रम और संविदा मजदूरी के बढ़ते इस्तेमाल के खिलाफ दृढ़ संघर्ष कर रहे हैं।

IT मज़दूर, स्वास्थ्य सेवा मज़दूर, म्युनिसिपल मज़दूर, स्कूल और कॉलेज टीचर्स सभी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद इज्ज़तदार ज़िंदगी के लिए पेंशन और दूसरी तरह की सामाजिक सुरक्षा की मांग श्रमजीवी कर रहे हैं।

12 फरवरी को, देश भर के किसानों सहित मेहनतकश लोगों ने अपनी रोज़ी-रोटी और अधिकारों पर बढ़ते हमलों का विरोध करने के लिए एक बड़ी आम हड़ताल में हिस्सा लिया।

मज़दूरों और किसानों की त्वरित आर्थिक मांगों के लिए एक समान मंच पर बढ़ती एकता, एक बहुत ही सकारात्मक बात है। पूंजीपति वर्ग और उसकी राजनीतिक पार्टियां धर्म, जाति, भाषा, आदिवासी पहचान या नस्ल के आधार पर मेहनतकश लोगों के बीच झगड़े भड़काकर इस एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं।

हमारा धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या भाषा कुछ भी हो, हम सभी जो अपनी श्रमशक्ति बेचकर जीते हैं, एक ही वर्ग, यानी श्रमजीवी वर्ग के हैं। हमारी लड़ाई पूंजीपति वर्ग के खिलाफ है, और किसानों की भी लड़ाई पूंजीपति वर्ग के खिलाफ़ ही है। पूँजीपतियों के हित मज़दूरों और किसानों के हितों के बिल्कुल उलटे हैं। यही सच है, जिसे भाजपा, कांग्रेस और पूंजीपति वर्ग की दूसरी पार्टियां छिपाने की कोशिश करती हैं।

मजदूर साथियों!

हम, कामगार और किसान, इस देश की आबादी का 90 प्रतिशत से भी ज़्यादा हिस्सा हैं। फिर भी, हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती। केंद्र और राज्यों में सरकारें बदलने से भी अर्थव्यवस्था की दिशा नहीं बदली है; यह दिशा हमेशा से पूंजीपतियों के मुनाफ़े को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की रही है। पूंजीवादी पार्टियां लोगों से वही वादे करती रहती हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन सरकार बनाने के बाद वे ठीक उसका उल्टा करती हैं–सिर्फ़ पूंजीपतियों की सेवा करती हैं। वे उन मतदाताओं के प्रति जवाबदेह नहीं हैं जिनके प्रतिनिधि होने का वे दावा करती हैं। दावों के विपरीत, हम देख सकते हैं कि इस लोकतंत्र में, हम आम लोगों के पास कोई ताक़त नहीं है; नीतियां और कानून ठीक हमारे हितों के विपरीत और शासक पूंजीपति वर्ग के हितों के लिए बनाए जाते हैं।

चुनावों के ज़रिए नौकरशाही, सुरक्षा बलों, न्यायपालिका और राज्य के अन्य सभी अंगों की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आता। ब्रिटिश शासन के समय से लेकर आज तक, वे मेहनतकश लोगों की क़ीमत पर शोषकों के हितों की रक्षा करते आए हैं।

जहां एक ओर हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है–और यहां तक कि श्रमजीवी वर्ग की पिछली पीढ़ियों ने संघर्षों के ज़रिए जो कुछ हासिल किया

है, उसे बचाए रखने के लिए भी जूझना पड़ता है–वहीं दूसरी ओर हमें पूंजीपतियों के शासन को हटाकर मजदूरों और अन्य मेहनतकश लोगों का शासन स्थापित करने के लिए भी काम करना होगा।

मौजूदा पूंजीवादी-लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदलने की ज़रूरत है–एक ऐसी व्यवस्था जो श्रमजीवी वर्ग को सत्ता में बनाए रखने के लिए तैयार की गई हो। राजनीतिक प्रक्रिया को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि मेहनतकश लोगों का अपने चुने हुए प्रतिनिधियों और उनके द्वारा लिए गए फ़ैसलों पर सीधा नियंत्रण हो। चुनावों का खर्च सार्वजनिक कोष से उठाया जाना चाहिए। हर निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की, उम्मीदवारों के चयन में निर्णायक भूमिका होनी चाहिए। हमें यह अधिकार मिलना चाहिए कि यदि हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि हमारे हितों के अनुसार काम नहीं करता, तो हम उसे किसी भी समय वापस बुला सकें।

जब राजनीतिक सत्ता हमारे हाथों में होगी, तो हम अर्थव्यवस्था के उद्देश्य और दिशा को बदलने में सक्षम होंगे–पूंजीवादी मुनाफ़े को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के बजाय, हम अर्थव्यवस्था को सभी मेहनतकश लोगों की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में मोड़ देंगे।

मजदूर साथियों!

मई दिवस 2026 के अवसर पर, आइए, हम अपनी आजीविका और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष को और तेज़ करने का संकल्प लें!

आइए, हम हिन्दोस्तान की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के, सभी यूनियनों और संगठनों के, और राज्यों के मजदूरों की एकता को मज़बूत करें और पूंजीवादी वर्ग के उस मंसूबे को नाकाम करें जिसके तहत वे हमें जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर बांटना चाहते हैं! आइए, हम सब के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने हेतु मज़दूरों और किसानों का शासन स्थापित करने के उद्देश्य से अपना संघर्ष जारी रखें!